प्रेषक.

मनीषा पंवार, सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग—7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक । ६ अप्रैल, 2014 विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 318/xxvii(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 एवं आपके पत्र संख्या -डिग्री बजट-163/2014-15 दिनांक 03.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रू० 4277.90 लाख एवं रू० 16293.65 लाख अर्थात कुल रू० 20571.55 लाख (रूपये दो अरब पांच करोड़ इक्कहत्तर लाख पच्चपन हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा, धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों / शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अविध के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(5) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—2015 के आय —व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं के लेखाशीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक / सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—318/xxvii(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नःयथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार) सचिव

पृ०सं० 12.02 (1) / xxiv(7)—17(2) / 2014 तद्दिनांक । प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— आयुक्त कुमांयू एवं गढवाल उत्तराखण्ड।

3- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

4- कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।

5- वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।

6- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।

7- निदेशक एन०आई०सी० सचिवालय उत्तराखण्ड।

8- गाई फाईल।

आज्ञा से (लक्ष्मण सिंह) उप सचिव